



एक कदम पारदर्शिता की ओर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग

न्यूजलेटर - सितंबर - 2022



National Commission For Scheduled Castes
5th Floor, Lok Nayak Bhawan, Khan Market,
New Delhi-110 003

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग न्यूजलेटर

वर्ष: 02 अंक: 04 सितंबर 2022

संपादक
राजेश रंजन सिंह

ई-मेल : singh.rr9@gmail.com
[@srajeshranjan](https://twitter.com/srajeshranjan)

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग अपनी मासिक पत्रिका के जरिए लोगों तक अहम जानकारीयां पहुंचाने का काम लगातार कर रहा है। आयोग अभी तक सफलतापूर्वक पंद्रह अंक प्रकाशित कर चुका है। यह सोलहवां अंक होगा। इस अंक में हमने आयोग और वित्तीय सेवाएं विभाग के साथ हुई बैठक में लिए गए अहम फैसलों को प्रकाशित किया है। ये फैसले अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों के लिए काफी लाभकारी होंगे। इसके अलावा आयोग द्वारा अनुसूचित जाति आरक्षण नीति का कार्यान्वयन के लिए समीक्षा बैठक, राज्य कार्यालयों में मामलों की सुनवाई, मुख्यालय में कार्य कुशलता बढ़ाने के लिए उठाए गए कदमों, गंभीर मामलों में स्थलीय निरीक्षण, सोशल मीडिया के जरिए अनुसूचित जाति के लोगों के साथ होने वाली घटनाओं पर मांगी गई रिपोर्ट को शामिल किया है। आयोग की कोशिश है कि इन सभी मामलों की जानकारी आम लोगों तक भी पहुंचती रहे, इसी को ध्यान में रखते हुए मासिक पत्रिका का प्रकाशन जारी है। आपका यह सहयोग आगे भी मिलते रहे, इसकी हम अपेक्षा करते हैं।

धन्यवाद

(संपादक)

किसी भी प्रकार के सुझाव और शिकायतों के
लिये संपर्क करें:

011 - 24620435 & 24606802

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
भारत सरकार

5th Floor, Lok Nayak Bhawan, Khan Market,
New Delhi - 110003

website: <http://ncsc.nic.in>

ऑनलाइन शिकायत यहां दर्ज करें:
<https://ncsc.nedg.in/>

02 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग - न्यूजलेटर

National Commission for Scheduled Castes



**SHRI VIJAY SAMPLA
CHAIRMAN**



**SHRI ARUN HALDER
VICE CHAIRMAN**



**DR. ANJU BALA
MEMBER**



**SHRI SUBHASH
RAMNATH PARDHI
MEMBER**



डॉ. भीमराव अंबेडकर



@NCSC_GoI



@NCSC.GoI



@ncsc_goi

माननीय अध्यक्ष का संदेश

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग द्वारा प्रकाशित मासिक पत्रिका के सोलहवें अंक के विमोचन के लिए यह संदेश लिखते हुए मुझे अपार प्रसन्नता हो रही है। आयोग लगातार अनुसूचित जाति के लोगों को न्याय दिलाने के लिए देश के विभिन्न राज्यों में स्थलीय निरीक्षण से लेकर आयोग मुख्यालय में जनसुनवाई और सभी संभव प्रयास कर रहा है।

सितंबर माह में आयोग ने माननीय केंद्रीय वित्तमंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी के साथ मिलकर अनुसूचित जातियों हेतु ऋण एवं अन्य कल्याणकारी योजनाओं पर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थाओं की समीक्षा बैठक की गई। इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए जोकि अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों के लिए काफी लाभकारी साबित होंगे। इसी बैठक में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा अनुसूचित जाति समुदाय से संबंधित व्यक्तियों को ऋण देने के प्रयासों की समीक्षा करने के साथ साथ रिक्तियों में आरक्षण का बैकलॉग भरने, दलित कर्मचारियों का शिकायत निवारण तंत्र और उनके कल्याण के लिए किए गए विभिन्न उपायों की समीक्षा की गई।

इसी बैठक में यह फैसला लिया गया कि बैंक बैकलॉग रिक्तियों को भरने के लिए 2 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक अभियान चलाएंगे। साथ ही, बैंकों को 31 अक्टूबर तक इस अभियान के दौरान अनुसूचित जाति की लंबित शिकायतों को दूर करने और पूरा करने का निर्देश दिया गया है। यह भी फैसला लिया गया कि केंद्र सरकार के स्टैंड अप इंडिया कार्यक्रम के अनुसार, बैंकों की शाखाएं उन्हें सौंपे गए लक्ष्यों, विशेष रूप से अनुसूचित जाति समुदाय के सदस्यों के प्रति दायित्वों को पूरा करेंगी।

इसके अलावा आयोग के समक्ष अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों के साथ अत्याचार की कई घटनाएं शामिल हैं। जिनमें उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी के निघासन में दो बहनों को घर से अगवाह करने के बाद दोनों की लाश मिलने की घटना प्रमुख हैं। इस घटना पर आयोग का एक दल निघासन पहुंचा और सख्त कार्रवाई के निर्देश जारी किए। इसके अलावा सोशन मीडिया के माध्यम से मिली घटना की जानकारी पर संज्ञान लेते हुए नोटिस जारी किया गया। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग समाज के हाशिये पर खड़े वर्ग के लोगों को न्याय दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है और आयोग का प्रयास रहेगा कि दूरस्थ गांव से लेकर शहर तक के प्रत्येक अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों के साथ किसी प्रकार का भेदभाव या अन्याय न होने पाए।

मासिक पत्रिका के जरिए हमारी कोशिश रहती है कि लोगों तक आयोग द्वारा लिए गए फैसलों और गतिविधियों के बारे में जानकारी समय-समय पर पहुंचती रही। आयोग ठीक से काम करता रहे, इसके लिए आशा है कि आपका सहयोग मिलता रहेगा।

जय हिंद !

सादर धन्यवाद



SHRI VIJAY SAMPLA
CHAIRMAN

विजय सांपला

अध्यक्ष,
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
भारत सरकार

समीक्षा बैठक



DFS-आयोग की समीक्षा बैठक

केंद्रीय वित्तमंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग अध्यक्ष श्री विजय सांपला द्वारा अनुसूचित जातियों हेतु ऋण एवं अन्य कल्याणकारी योजनाओं पर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थाओं की समीक्षा बैठक की गई। इस बैठक में आयोग की माननीय सदस्या डॉ. अंजू बाला व माननीय सदस्य श्री सुभाष रामनाथ पारधी मौजूद रहे। समीक्षा बैठक में वित्तीय सेवाएं विभाग व आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सभी सार्वजनिक बैंकों के प्रमुख भी मौजूद रहे। इस बैठक में यह समीक्षा की गई कि अनुसूचित जाति के लोगों को बैंक किस तरह लोन बांटता है और उन्हें सरकारी योजनाओं का उचित लाभ मिल रहा है या नहीं। अनुसूचित जाति के लिए चल रही सरकारी योजनाओं व बैंकों में अनुसूचित जाति वर्ग के खाली पड़े पदों को लेकर भी बैठक में समीक्षा की गई।





केंद्रीय वित्तमंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग अध्यक्ष श्री विजय सांपला द्वारा अनुसूचित जातियों हेतु ऋण एवं अन्य कल्याणकारी योजनाओं पर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थाओं की समीक्षा बैठक की गई। इस बैठक में लिए गए फैसलों के संबंध में माननीय अध्यक्ष श्री विजय सांपला व माननीय सदस्या डॉ. अंजू बाला प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए।

आयोग में हिंदी पखवाड़े का आयोजन



राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग में 14 सितंबर 2022 से लेकर 29 सितंबर 2022 तक हिंदी पखवाड़े का आयोजन किया गया। पखवाड़े के अवसर पर विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं, हिंदी निबंध लेखन, हिंदी वाद विवाद प्रतियोगिता, हिंदी टिप्पण एवं आलेखन (व्यवहारिक), राजभाषा ज्ञान/सामान्य हिंदी ज्ञान, हिंदी श्रुतलेख, हिंदी कविता पाठ, हिंदी समाचार वाचन, लघु फिल्म (आयोग के कार्यों से संबंधित) प्रतियोगिता आयोजित की गई। इस हिंदी प्रतियोगिता में आयोग के स्टाफ ने बढ़-चढ़कर भाग लिया। बता दें कि प्रतियोगिता में प्रथम द्वितीय और तृतीय पुरस्कार पाने वाले विजेताओं को प्रोत्साहन राशि व पुरस्कार दिए गए।

सोशल मीडिया से संज्ञान

Vijay Sampla @thevijaysampla · Sep 2
सोशल मीडिया पर चल रही इस खबर का संज्ञान लिया है। @Jhal जारी करते हुए मामले की विस्तृत जानकारी मांगी है।

Ashok Das @ashokdasDDastak · Sep 1
दलितों ने ठेका नहीं लिया है कि "बहुजन समाज" बनाने के नाम खाते रहें।
झारखंड के पलामू से खबर है कि मुसलमानों ने दलित समाज के गांव से भगा दिया है, जिससे वो जंगल में रहने को मजबूर हैं।
[Show this thread](#)



पूपा: दो दलित बहनों को घर के बाहर से अगवा कर ले गए बाइक सवार, कुछ दूर बाद पड़ पर लटकी मिली दोनों की लाशें

themooknayak.in/dead-bodies-of-...

Vijay Sampla @thevijaysampla · Sep 15



Vijay Sampla @thevijaysampla · Sep 17
आरोप गंभीर है। @D... भिजवाएं।

The Dalit Voice
#Horrific In a temple private parts of a child frequently matchsticks to



Vijay Sampla @thevijaysampla · Sep 17
अति दुखद समाचार @RajPoliceHelp मामले की विस्तृत जानकारी @NCSC_GoI को तुरंत अवगत करवाएं। इस अति जल्दी की

News18 Rajasthan @News18Rajasthan · 4
जैसलमेर के मोहनगढ़ में मटकी से घली पीने पर दलित यु...
आरोपियों ने जल से मारने की नीयत से कायर भी किया
@JaisalmerPolice @RajPoliceHelp @RajCMO @NCSC_GoI @thevijaysampla @OmJaisalmer @hemantkumarnews



Vijay Sampla @thevijaysampla · Sep 17
अति निंदनीय घटना है। @AlwarPolice, वायरल वीडियो का स्वतः संज्ञान लिया है। घटना की जानकारी एवं अब तक की गई कार्यवाही से @NCSC_GoI को बिना विलंब सूचित करें।

Suraj Kumar Baudh @SurajKrBaudh · Sep 17
देश में 'भारत जोड़ो यात्रा' और राजस्थान में SC लोगों पर जुलूम करो। बस यही कांग्रेस की सच्चाई है।

अलवर में सरपंच हाजिम ने एक SC युवक को भरी सभा में जूतों से मारा। सरकार तमाशबीन बनी हुई है। ऐसी घटनाओं पर सब लोग खामोश क्यों हो जाते हैं?





पलामू में घर तोड़कर भगाया, आयोग ने की जांच

झारखंड राज्य के पलामू जिले के पांडू थाना क्षेत्र अंतर्गत मुसुमातू गांव में 20 दलित परिवारों के डेढ़ दर्जन घर ध्वस्त कर दिए। बताया गया कि ज्यादातर घर मिट्टी और फूस के थे, जिनमें ये परिवार पिछले तीन-चार दशकों से रह रहे थे। दलितों ने घरों को ध्वस्त करने का विरोध किया तो उनके साथ मारपीट भी गई। उजाड़े गए लोगों को गाड़ियों पर लादकर एक जंगल के पास छोड़ दिया गया। मीडिया में आई इस खबर पर संजान लेते हुए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का एक दल स्थलीय जांच के लिए मुसुमातू गांव पहुंचा। दल की अगुवाई माननीय उपाध्यक्ष श्री अरुण हालदार ने की। स्थलीय जांच के बाद जिला प्रशासन को अनुसूचित जाति के लोगों को पुनः उसी जमीन पर तब तक के लिए जब तक की जमीन के संबंध में विवाद समाप्त नहीं हो जाता है तब तक बसाई जाने का निर्देश दिया गया। साथ ही यह निर्देश भी दिया गया कि जब तक अनुसूचित जाति के लोगों को पुनर्वास नहीं कर दिया जाता है तब तक उन्हें जिला प्रशासन की तरफ से राशन एवं अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। घटना के प्राथमिकी नामजद शेष अभियुक्तों को शीघ्र गिरफ्तार करने का भी निर्देश दिया गया। पीड़ित परिवारों का आधार कार्ड, बैंक अकाउंट आदि पुराने पते पर ही निर्गत करने के निर्देश दिए गए।



तेलंगाना में अत्याचार व उत्पीड़न के मामलों की सुनवाई

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के माननीय उपाध्यक्ष श्री अरुण हालदार ने तेलंगाना राज्य का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने राज्य में हुए अत्याचार व उत्पीड़न के बीस मामलों की सुनवाई की। उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों को उचित धाराओं के अंतर्गत पूर्ण न्यायिक जांच करने एवं दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया। इसके अलावा माननीय उपाध्यक्ष ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ भी बैठक की। इस दौरान माननीय उपाध्यक्ष अरुण हालदार ने इन अधिकारियों के साथ अनुसूचित जाति के लोगों से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की।



निघासन कांड पर आयोग की सख्ती, दिए जल्दी कार्रवाई के निर्देश

उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी के निघासन में दो बहनों को घर से अगवाह करने के बाद दोनों की मिली लाशों। मीडिया के जरिए मिली इस घटना की जानकारी के बाद मामले की गंभीरता को समझते हुए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का एक दल निघासन पहुंचा।

दल की अगुवाई आयोग की माननीय सदस्या डॉ. अंजू बाला ने की। माननीय सदस्या पीड़ित परिवार से मिलीं और घटना का स्थलीय निरीक्षण भी किया। माननीय सदस्या ने घटना से संबंधित दोषियों के

विरुद्ध कठोर कानूनी कार्यवाही हेतु प्रशासन को आदेश दिया। साथ ही परिवार को यह भरोसा दिलाया कि उन्हें न्याय दिलाया जाएगा, कानूनी प्रक्रिया में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जायेगी।

लखीमपुर खीरी दौरे के दौरान माननीय सदस्या ने जिला प्रशासन के सभी वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी की और निघासन में हुई घटना पर न्यायपूर्ण निस्तारण हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया।



महेंद्र छात्रावास गोलीकांड में आयोग पहुंचा घटना स्थल

बिहार के पटना में महेंद्र स्थित राजकीय आंबेडकर छात्रावास के छात्रों और बकरिया टोला के लोगों के बीच मारपीट और फायरिंग मामले में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का एक स्थलीय निरीक्षण करने पहुंचा। माननीय सदस्या डॉ. अंजू बाला की अगुवाई में दल ने घटना में घायल अनुसूचित जाति वर्ग के छात्रों के संबंध जानकारी मांगी। उन्होंने सर्किट हाउस पटना में जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहित जिला प्रशासन के सभी वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों के साथ छात्रावास महेंद्र में हुए गोलीकांड पर समीक्षा बैठक की और संबंधित अधिकारियों को अविलम्ब कार्यवाही हेतु निर्देशित किया। इस दौरान छात्रों ने अपनी समस्याओं से संबंधित एक ज्ञापन पत्र भी माननीय सदस्या को सौंपा।

लोगों ने बताई अपनी समस्याएं

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के माननीय उपाध्यक्ष श्री अरुण हालदार ने नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग मुख्यालय में आए लोगों के साथ अधिकारियों की उपस्थिति में बैठक की। इस बैठक में उन्होंने लोगों से उनकी समस्याओं को जाना। माननीय उपाध्यक्ष ने समस्याओं को दूर कराने के लिए भरोसा दिलाया।

आयोग के दल ने किया गाजियाबाद का दौरा

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की माननीय सदस्य डॉ. अंजू बाला ने उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले का दौरा किया। इस दौरे के दौरान जिला प्रशासन के सभी वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक कर अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की समस्याओं एवं उनके समाधान करने हेतु निर्देशित किया।



आयोग मुख्यालय में समस्याएं सुनीं

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के माननीय सदस्य श्री सुभाष रामनाथ पारधी ने नई दिल्ली स्थित आयोग मुख्यालय में लोगों की जन समस्याएं सुनीं। इसके बाद माननीय सदस्य ने उनकी समस्याओं पर संज्ञान लेते न्यायोचित कार्यवाही कर मामलों का निस्तारण किया। इस दौरान आयोग के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे।





Author's address: Institute of Information Systems
University of Bonn
Sigmund-Freud-Str. 1
D-53117 Bonn, Germany
christian.schneid@uni-bonn.de

the notice issued to authorities in U.F., the NCSC said it had decided to independently investigate the incident with officials in the know saying

panied by Director NCSC, Sanjay Kumar Singh, and other staff
e commission. Besides holding a meeting with Vice Chancellor,
of Nazir Ahmad Ganai, directors and deans of the university, she held
actions with the SC and ST category employees and students.

...सोओ संजयनाथ
...ओ एकेका मिह और
...मन खादा मौसुम से।
...ह ने अफसोसों से भी
...खावारी भी।

श्रवण में कहा गया पुनः सीटनशी के प्रस्ताव सरकार ने मन्त्र के सभी वर्गों के समीक्षा किया

लोहो ने कहा कि बसिंधी को बाढ़ खोदने के लिए जिस तरह का कुत्तोला जकाय था, वैसा ही कुत्तोला जका जलयंत्र बाढ़ो को अलग करने वाले बसिंधी के घाटी पर खोदने को संभव की। इस पर डॉ० अन्सुमान ने प्रसंगी पुराणीय विज्ञान का अध्ययन किया और कहा कि अगर अरोहिणियों के का अर्थ रूप है अर्द्धांग बसिंधी से बनता था, तो तब काली की आर्वा की जगह में अनेक हिले से अनेक घाटी का जल अलग होकर अरोहिणियों की ओर बहने लगा।

[illegible]

खबरों में आयोग

PSU banks to start drive from October 2 to fill back vacancies of Scheduled Castes: NCSC chief

By PTI

ANUSUCHIT JATIYON HETU VITTA MANTRI AUR RAASHTRIY AUVAN KALYAN KOSHNAON PER SARVJANIK K...

Review Meeting Finance Minister and Scheduled Caste with Public Se... Ba... Other Welfa...

7 सितंबर, 20...

महम सीध, ना...

From Oct 2, PSBs to begin drive to fill backlog in SC vacancies: NCSC Chairman Vijay Sampla

Vijay Sampla said PSBs will send a report on reservation policy, about recruitment and coverage of SC beneficiaries in all the schemes, and submit the progress of all the schemes to the NCSC, twice every year.

PSU banks to start drive from Oct 2 to fill backlog vacancies of scheduled castes: Sampla

The NCSC Chairman Vijay Sampla said that the PSU banks will start a drive from October 2 to fill the backlog vacancies of Scheduled Castes (SC) in all the schemes. He said that the banks will send a report on reservation policy, about recruitment and coverage of SC beneficiaries in all the schemes, and submit the progress of all the schemes to the NCSC, twice every year. He also said that the banks will start a drive from October 2 to fill the backlog vacancies of Scheduled Castes (SC) in all the schemes. He said that the banks will send a report on reservation policy, about recruitment and coverage of SC beneficiaries in all the schemes, and submit the progress of all the schemes to the NCSC, twice every year.

PSU banks to start drive from Oct 2 to fill backlog vacancies of scheduled castes: Sampla

The NCSC Chairman Vijay Sampla said that the PSU banks will start a drive from October 2 to fill the backlog vacancies of Scheduled Castes (SC) in all the schemes. He said that the banks will send a report on reservation policy, about recruitment and coverage of SC beneficiaries in all the schemes, and submit the progress of all the schemes to the NCSC, twice every year. He also said that the banks will start a drive from October 2 to fill the backlog vacancies of Scheduled Castes (SC) in all the schemes. He said that the banks will send a report on reservation policy, about recruitment and coverage of SC beneficiaries in all the schemes, and submit the progress of all the schemes to the NCSC, twice every year.

| सरकारी बैंक में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित पदों को 31 दिसंबर तक भरा जाएगा- विजय सांपला

29 Sep 2022 18:13:23

जामरण



Bank Jobs: सरकारी बैंक 31 दिसंबर तक भरेंगे एससी के बैकलाग पदों की रिक्तियां

Author: Anurag

Updated Date: 29 Sep 2022 18:13:23

Updated Date: 29 Sep 2022 18:13:23

BANK JOBS

नई दिल्ली, 29 सितंबर (हि.स.)। सरकारी बैंक में अनुसूचित जाति के लोगों के लिए आर 31 दिसंबर तक भरा जाएगा। इस संबंध में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने वित्त मंत्रालय 31 दिसंबर तक बैंक को एससी की रिक्तियों को भरने की बात कही है।

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष विजय सांपला ने मुख्य रूप से कहा कि केन्द्र सर और प्रशासनिक इकाइयों में एससी की रिक्तियों को भरने की दिशा में काम शुरू बैंक में एससी की रिक्तियों को भरने की दिशा में काम शुरू हुआ है। वित्त मंत्रालय ने सभी अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक एससी की रिक्तियों का सर्वे करने को कहा है। इसके बाद से भरने के निर्देश जारी हुए हैं। उन्होंने बताया कि बैंक की तब पर बाकी स्थानों पर भी अनुसू लिए आरक्षित पदों को भरने की दिशा में काम शुरू होगा।

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (एनएससीआई) के अध्यक्ष विजय सांपला ने बताया कि आयोग की जांच के बाद पता जाती है कि कितने रिक्त हैं। सभी सरकारी बैंकों के आयोगों ने प्रमाणित रिक्तियों के साथ एक नए में एक बैंक को 31 दिसंबर तक रिक्तियों को भरना है।

जामरण मुद्रा, नई दिल्ली। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (एनएससीआई) की जांच के बाद सरकारी बैंकों ने 31 दिसंबर तक अनुसूचित जाति (एनएससी) के रिक्त पदों को भरने की बात कही है। इसकी शुरुआत 2 अक्टूबर से होगी। इसके साथ ही सरकारी बैंकों ने एक ही नए रिक्त रिक्तियों को भी 31 अक्टूबर तक पूरा करने का आदेश दिया है।

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष ने दी जानकारी

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (एनएससीआई) के अध्यक्ष विजय सांपला ने मुख्य रूप से कहा कि सरकारी बैंकों ने 31 दिसंबर तक रिक्तियों को भरने की बात कही है। इसकी शुरुआत 2 अक्टूबर से होगी। इसके साथ ही सरकारी बैंकों ने एक ही नए रिक्त रिक्तियों को भी 31 अक्टूबर तक पूरा करने का आदेश दिया है।

PSBs to launch special campaign for scheduled castes; issues including welfare schemes, backlog vacancies, loan disbursement to be taken up

During details of the meeting, NCSC Chairman Vijay Sampla said banks have been directed to clear and complete the pending grievances of SCs by October 31.

SBI

Best & Bright

ETNews News Service

News India, Correspondent: D

National Commission for Scheduled Castes (NCSC) Chairman Vijay Sampla on Monday instructed that all the Public Sector Banks (PSBs) should start from October 2, 2022 to fill up the backlog vacancies of Scheduled Castes.

Sampla made the statement in a meeting (convened by the Union Minister for Finance) held in New Delhi on Monday. He said that the PSBs should start from October 2, 2022 to fill up the backlog vacancies of Scheduled Castes.

PRESS TRUST OF INDIA

एससी के पुराने रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए सार्वजनिक बैंक दो अक्टूबर से चलाएंगे अभियान

नई दिल्ली, 29 सितंबर (एनएससीआई) के अध्यक्ष विजय सांपला ने बताया कि सरकारी बैंकों ने 31 दिसंबर तक रिक्तियों को भरने की बात कही है। इसकी शुरुआत 2 अक्टूबर से होगी। इसके साथ ही सरकारी बैंकों ने एक ही नए रिक्त रिक्तियों को भी 31 अक्टूबर तक पूरा करने का आदेश दिया है।



माननीया केंद्रीय वित्तमंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी के साथ बैठक करते माननीय अध्यक्ष श्री विजय सांपला जी।



आयोग के मुख्यालय में माननीय अध्यक्ष श्री विजय सांपला जी वित्तीय सेवाएं विभाग के सचिव और संयुक्त सचिव के साथ बैठक करते हुए। साथ में आयोग के संयुक्त सचिव श्री ज्ञानेश्वर कुमार सिंह भी मौजूद रहे।

National Commission For Scheduled Castes

**5th Floor, Lok Nayak Bhawan, Khan Market,
New Delhi-110 003**